दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 05 अक्टूबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 10

महत्वपूर्ण एवं खास

बेंगलुरु में 15 स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी

बेंगलुरु (आरएनएस)। आयकर विभाग (आईटी) ने बुधवार सुबह बेंगलुरु में 15 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। अधिकारी कुछ उद्योगपतियों के आवासों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी कुछ उद्योगपतियों और सोने के व्यापारियों द्वारा कर चोरी की पृष्ठभूमि में की गई है। मंगलवार रात चेन्नई और मुंबई कार्यालय से अधिकारी यहां पहुंचे। छापेमारी विजयनगर, हुलीमावु, सदाशिवनगर और सांकी टैंक इलाकों में की गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि छापेमारी एक महिला दंत चिकित्सक के आवास पर भी की जा रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला : लालू परिवार को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए सभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। मामले का ट्रायल 16 अक्टूबर से शुरू होगा। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती समेत लैंड फॉर जॉब केस के सभी 17 आरोपी बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर सभी को पिछले महीने समन किया था। सभी आरोपियों ने कोर्ट में बुधवार को जमानत की अर्जी दी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। साथ ही 16 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस दिन से केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की ओर से कोर्ट में दलील दी गई की उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि अभी आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, कहा- इस मुद्दे पर न करें राजनीति

नई दिल्ली (आरएनएस)। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न करे। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट हल की तरफ बढ़ रहा है तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा हालात कैसे हैं।

रसायन के नोबेल का ऐलान, मोंगी बावेंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को मिलेगा

स्टॉकहोम। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को देने का ऐलान कर दिया गया है। इन्हें ये पुरस्कार छोटे क्वांटम डॉट्स पर उनके काम के लिए दिया जा रहा है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हंस एलेग्रेन ने बुधवार को इस पुरस्कार की घोषणा की। इससे पहले बीते सोमवार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का एलान किया गया था। इस साल कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया। इस खोज की वजह से कोरोनावायरस यानी सीओवीआईडी-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में मदद मिली।

वायु सेना को मिला पहला 'तेजस ट्विन सीटर' एयरक्राफ्ट : हर मौसम में भर सकेगा उड़ान

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना को अपना पहला 2 सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस ट्विन सीटर' मिल गया है। बुधवार को यह विमान आधिकारिक तौर पर भारतीय वायु सेना को सौंपा गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने बुधवार को वायु सेना को पहला तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर विमान सौंपा हैं।

तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर विमान एक हल्का विमान है। इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल 18 ट्विन सीटर विमान का ऑर्डर दिया गया था। भारतीय वायु सेना द्वारा दिए गए इस आर्डर में से 8 विमान अगले साल तक दे दिए जाने हैं। शेष 10 विमानों को 2026-27 तक इंडियन एयर फोर्स के सुपुर्द किया जाएगा।

गौरतलब है कि भारतीय सेना के पास एलसीए तेजस का एडवांस्ड वर्जन मार्क-1 ए विमान पहले से ही है। एयर फोर्स के पास उपलब्ध यह विमान एक फाइटर जेट है जो 2205 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा में उड़ता है। यही नहीं एयर फोर्स का यह फाइटर जेट 6 तरह की मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से 31 मिल चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क -1 हैं।

जबकि बुधवार को एयरफोर्स को सौंपा गया, तेजस टू-सीटर ट्रेनिंग विमान है। हालांकि ट्रेनिंग विमान होने के बावजूद आपातकालीन स्थिति में इसे बतौर फाइटर जेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले मंगलवार को एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि वायुसेना 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1ए खरीदने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल चौधरी ने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना को रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम की तीन यूनिट मिलीं। वायुसेना को अगले साल तक मिसाइल सिस्टम की शेष दो और यूनिट मिलने की उम्मीद है।

एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने यह भी कहा कि भारतीय वायु सेना अगले सात-आठ वर्षों में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये के सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हार्डवेयर को शामिल करने पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अनिश्चित जियोपोलिटिकल स्थिति ने एक मजबूत सेना की आवश्यकता को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना क्षेत्र में भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने का आधार बनी रहेगी। अग्निपथ योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। थिएटराइजेशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है।

मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

अब सिर्फ 603 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने बुधवार को उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया, जिसकी बुधवार को बैठक हुई थी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी मौजूदा 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है। 29 अगस्त को सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी।

उज्ज्वला लाभार्थियों को वर्तमान में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 703 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बाजार मूल्य 903 रुपये है। बुधवार के फैसले के बाद अब एक लाभार्थी को 603 रुपये का भुगतान करना होगा। 300 रुपये की बढ़ी हुई सब्सिडी सीधे उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

दर्दनाक हादसा: ट्रक और अर्टिका कार के बीच भीषण भिड़ंत, आठ लोगों की मौत

वाराणसी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार भोर एक भीषण सडक़ हादसे में आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को जीवित बचे लोगों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र के करखियांव क्षेत्र में आज भोर करीब साढ़े चार बजे जौनपुर-लखनऊ राजमार्ग पर ट्रक और अर्टिका कार की भिड़ंत में आठ लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक तीन वर्षीय बालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान विपिन यादव, उनकी मां गंगा यादव, महेंद्र वर्मा, उनकी पत्नी चंद्रकली, राजेंद्र यादव और तीन अन्य के रूप में की गई है। सभी हताहत पीलीभीत के निवासी बताये जाते हैं जो वाराणसी की धार्मिक यात्रा पर आये थे।

आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 78 हॉस्पिटल सूची से हटाए गए, 250 को शो-कॉज; 89 ने भरा जुर्माना

रांची (आरएनएस)। झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 400 से भी ज्यादा हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। 78 हॉस्पिटलों को गड़बड़ी करने के आरोप में डि-इम्पैनल्ड किया गया है। 89 हॉस्पिटलों से करीब एक करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि 250 से भी ज्यादा हॉस्पिटलों को शो-कॉज किया गया है। एक हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा है कि गड़बडिय़ों की जांच लगातार जारी है। जिन हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया है, अगर उनके प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खास बात यह है कि दो महीने पहले लोकसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में भी झारखंड के हॉस्पिटलों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था। रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने 250 ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर पैसा उठाया, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी।

राज्य के 47 हॉस्पिटल्स ने एक-एक दिन में अपनी कुल बेड क्षमता की तुलना से ज्यादा मरीजों के इलाज के नाम पर योजना का लाभ लिया। सावित्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल की कुल बेड क्षमता 30 है। इसने एक दिन में योजना के तहत 103 मरीजों के इलाज का दावा किया।

इसी तरह किडनी केयर सेंटर में मात्र 12 बेड हैं, लेकिन इसने 55 मरीजों के इलाज का दावा किया। रांची के इरबा स्थित क्यूरी अब्दुर्रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट ने 100 बेड की क्षमता रखते हुए 112 मरीजों का इलाज दिखाया।

पलामू जिले के एक हॉस्पिटल ने योजना के तहत डि-इम्पैनल होने के बाद अपना नाम बदल लिया और 130 मरीजों के इलाज के दावा किया। कई मरीजों के इलाज के नाम पर इसने भुगतान भी उठा लिया।

नांदेड़ के बाद नागपुर के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 25 लोगों की मौत

नागपुर (आरएनएस)। नागपुर के सरकारी मेयो अस्पताल में विभिन्न कारणों से बुधवार सुबह तक 24 घंटे में कम से कम 25 मरीजों की जान चली गई, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने आज सुबह एक एक्स पोस्ट में नई मौतों पर प्रकाश डालते हुए कहा, डर यहीं खत्म नहीं होता है और स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है और सरकार सो रही है।

सुले ने कहा, ठाणे, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर (घटनाओं) के बाद अब नागपुर में भी 25 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के पास नई दिल्ली जाने का समय है, लेकिन इन अस्पतालों का दौरा करने का समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं के लिए महाराष्ट्र के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और राज्य में चिकित्सा आपूर्ति की कमी है।

संयोग से, नागपुर राज्य की दूसरी राजधानी है और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं का गृह नगर है।

अधिकारियों के अनुसार, इस बीच, डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (नांदेड़) में मरने वालों की संख्या बढक़र 35 हो गई, जबकि घाटी अस्पताल (छत्रपति संभाजीनगर) में मरने वालों की संख्या 10 से बढक़र 18 हो गई। विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार आज दो अस्पतालों के दौरे पर जाने वाले हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेता विपक्ष (विधान परिषद) अंबादास दानवे ने आज सुबह नांदेड़ अस्पताल का दौरा किया।

दानवे ने कहा कि मरीजों ने उन्हें अस्पताल की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया और बताया कि कैसे सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में देरी के कारण एक गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई।

राज्य में तीन दिन में तीन जिलों के तीन सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों, चिकित्सा या पैरामेडिकल स्टाफ की कथित कमी सहित विभिन्न खामियों के कारण लगभग 30 शिशुओं सहित कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया कि नांदेड़ अस्पताल में मौतों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़, सेना के 23 जवान लापता

गंगटोक (आरएनएस)। सिक्किम में लोनाक झील के ऊपर बुधवार को अचानक बादल फटने से कम से कम 23 सैनिक लापता हो गए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं और विवरण की पुष्टि करने के प्रयास जारी हैं।सेना के प्रवक्ता ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का स्तर अचानक 15-20 फीट बढ़ गया।

उन्होंने कहा, जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए हैं। फिलहाल 23 सैन्य कर्मियों के लापता होने और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की सूचना है। तलाशी अभियान जारी है। आपदा के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने 900 करोड़ के आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के मुलुगु में 900 करोड़ रुपये की लागत से सममक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को चुनावी राज्य तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान मुलुगु में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी।

पीएम मोदी ने एक समारोह के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम आदिवासी देवी सम्मक्का और सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पहल के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैं तेलंगाना के लोगों को उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इस साल दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की राज्य में ज्यादा राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। इसलिए पार्टी आक्रामक तरीके से राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।

पीएम मोदी पिछले एक सप्ताह में दो बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। जिससे पता चलता है कि भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर कितनी उत्साहित है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और विपक्षी कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय है।

यूजीसी फेलोशिप में बढ़ोतरी, 67,000 रुपए तक मिलेगी मासिक राशि

नई दिल्ली (आरएनएस)। इनोवेशन और रिसर्च नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शोधकर्ताओं को फेलोशिप के रूप में मिलने वाली की मासिक राशि बढ़ा दी है। यूजीसी के मुताबिक बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2023 से मान्य है।

यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पर जहां पहले 31,000 रुपए मासिक दिए जाते थे, उसे अब बढ़ाकर 37,000 महीना कर दिया गया है। इसी तरह से सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी सर्फ जो कि पहले 35,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 42,000 कर दिया गया है।

यूजीसी का कहना है कि रिसर्च एसोसिएट की फेलोशिप की राशि 47,000 प्रति माह से बढ़ाकर 58,000 कर दी गई है। जबकि, रिसर्च एसोसिएट ग्रेड 2 की फेलोशिप 49,000 से बढ़ाकर 61,000 कर दी गई है। इसी तरह रिसर्च एसोसिएट लेवल 3 की फेलोशिप, मासिक 54,000 से बढक़र 67,000 रुपए कर दी गई है।

इस निर्णय की जानकारी देते हुए यूजीसी ने कहा कि यह अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और शोधकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा। वहीं छात्र संगठनों ने भी यूजीसी के इस निर्णय की सराहना की है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ, वरिष्ठ शोध अध्येताओं व रिसर्च एसोसिएट की अध्येतावृत्तियों में बढ़ोतरी के निर्णय का स्वागत करती है।

गौरतलब है कि इससे पहले जब विज्ञान के विषयों के लिए फेलोशिप में बढ़ोतरी हुई थी, उसी समय यूजीसी से यह मांग की थी कि सभी फेलोशिप में बढ़ोतरी की जाए। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि शोधार्थियों की अध्येतावृत्तियों में बढ़ोतरी स्वागतयोग्य कदम है, भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने होंगे।